Feasibility Studies of Projects for J & K

193. SHRIMATI PARVATI DEVI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether feasibility studies of several projects for the Jammu and Kashmir State are lying with the Central Government; and

(b) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as it is received.

आगरे में जूते बनाने वाले कारखानों का बन्द होना

194. **श्री मनोहर लाल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण आगरे में जूते बनाने के 50 कारखाने लगभग बन्द होने की स्थिति में हैं और जिसके परिणामस्वरूप 50,000 लोग बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती): (क) जूतों पर उत्पादन शुल्क, उपकर (लेवी) लगाना कोई नई बात नहीं है तथा विद्यमान दरें बहुत समय से लागू हैं । ऐसे छोटे एकक को जिनमें 49 तक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा 2 अश्व शक्ति तक पावर का उपयोग किया जाता है, शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है । अत: उत्पादन शुल्क लगाने के कारण आगरा स्थित फुटवियर फैक्ट्रियों के बन्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमर जवान ज्योति पर व्यय

195. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति पर व्यय को किस शीर्ष के अन्तर्गत रखा जाता है ; और

(ख) गत दो वर्षों में इस पर कुल कितना खर्च हुआ है और इसके लिए कौन सी एजेन्सियां सरकार को धनराशि देती हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अमर जवान ज्योति पर गैस सिलैण्डरों, प्रति दिन पुष्पमाला अर्पित करने और वहां पर फहराये जाने वाले तीनों सेवाओं के झंडों को जब कभी आवश्यक हो बदलने पर व्यय होता है । इस व्यय को निम्नलिखित शीर्षों में रखा जाता है :—

(1) गैस सिलैण्डर

(2) प्रतिदिन पुष्पमाला अर्पित करने और जब कभी आवश्यक हो तो तीनों सेवाओं के झंडों को बदलने पर व्यय

थल सेना के बजट में डाला जाता है ।

पुष्पमाला और झंडों पर व्यय को तीनों सेनाओं के मुख्यालय अपनी गैर-सरकारी निधियों से पूरा करते हैं ।